ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

तनाव दूर करता है गुलदाउदी का फूल

रविवारीय, 22 - 28 दिसंबर 2019, वर्ष- एक, अंक-20, रांची कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्य 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से आप सबों को मैरी क्रिस्मस

झारखंड विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के हाथो भाजपा की करारी हार, रघुवर दास खुद अपनी सीट भी नहीं बचा सके

जलवायु परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन

जल जंगल जमीन की चिंतन वाली सरकार

जब पक्ष विपक्ष, चुनावी पंडित और जनता टीवी में नज़रें टिकाये झारखंड विधानसभा चुनावों के रिजल्ट को देख रहे थे तब झामुमो के नायक हेमंत सोरेन अपने आवास में निश्चिंत होकर बच्चों के साथ साइकित की सवारी कर रहे थे। उनकी सहजता से ऐसा लग रहा था जैसे ये रिजल्ट और प्रचंड जीत साइकिल चलाने इतना ही आसान है। हालांकि हेमंत सोरेन की निशचिंतता देख ये सब भले इतना आसान लग रहा था, लेकिन इस बेहतरीन जीत के पीछे हेमंत की बेजोड़ चुनावी रणनीति, महागठबंधन को तैयार करना और क्षेत्रवार परिश्रम का हाथ रहा। यही कारण है कि झामुमो ने उन क्षेत्रों में भी कुछ सीटें हासिल की जहां पहले उसकी पकड़ नहीं थी। झामुमो के इस बेहतरीन रणनीति ने यह भी सिद्ध किया कि हेमंत सोरेन अब राजनीति में परिपक्व नेता बन चुके हैं जिसके सामने भाजपा चारो खाने चित हो गयी।

मुख्य संवाददाता

रांची : झारखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार हुयी है। कांग्रेस ,झामुमो, राजद महागठबंधन ने भाजपा को जोरदार पटखनी दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुये 30 सीटें जीती हैं। हेमंत सोरेन इस जीत के नायक बन कर उभरे हैं।

कांग्रेस को भी झारखंड में16 सीटों के साथ संजीवनी मिली है। इसके पहले कांग्रेस झारखंड में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी उसके दो- दो प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार और सुखदेव भगत हाल के कुछ महिनों में पार्टी छोड़ कर चले गये थे। सुखदेव भगत तो कांग्रेस की चिरप्रतिद्वंदी भाजपा में चले थे। लेकिन इस जीत से जनता ने कांग्रेस को भी राज्य में यह भरोसा दिया है कि उसे जनता विकल्प के तौर पर देखती है। वहीं महागठबंधन की तीसरी सहयोगी राजद को प्राणवायु मिला है। हालांकि राजद को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली है लेकिन 2014 के चुनावों में साफ हो चुकी राजद का प्रदर्शन इस बार अच्छा रहा। मात्र छह सीटों पर चुनाव लड़ रही राजद ने झारखंड में फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है।

चुनावों में हार के बाद आत्ममंथन करने वाली परंपरा पर चलते हुये अब भाजपा अपनी हार का चिंतन कर रही है। लेकिन राज्य की जनता ने पहले ही यह बता दिया है कि दागी उम्मीदवारों को लाना, कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, सच बोलने वाले उम्मीदवारों को बेटिकट करना, कुछेक अफसरों के भरोसे पूरे सरकार को चलाना, बड़े-बड़े दावे करना, बेलगाम अफसरशाही और सिर्फ भव्य महोत्सवों, आयोजनों से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। इन सब के साथ ही किसी भी सरकार को अहंकार त्यागना होता है।

अब सुकून भरी है राह

झारखंड विधानसभा चुनावों में विजयी उम्मीदवारों की सूची

जमशेदपुर पूर्वी, सरयू राय(निर्दलीय)
चंदनकियरी से अमर बाउरी(बीजेपी)
बेरमो से राजेंद्र सिंह (कांग्रेस)
नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी (बीजेपी)
गोमिया से लंबोदर महतो (आजसू)
बहरागोड़ा से समीर महंती (जेएमएम)
डुमरी से जगन्नाथ महतो (जेएमएम)
कोलेबीरा से विक्सल कोंगाड़ी (कांग्रेस)
धनबाद से राज सिन्हा (बीजेपी)
तोरपा से कोचे मुंडा (बीजेपी)
बरहेट से हेमंत सोरेन (जेएमएम)
झरिया से पूर्णिमा सिंह (कांग्रेस)
शिकारीपाड़ा से नलिन सोरेन (जेएमएम)
गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर (जेएमएम)
सिंदरी से इंद्रजीत महतो (बीजेपी)
तमाड़ से विकास मुंडा (जेएमएम)
दुमका(एसटी) हेमंत सोरेन (जेएमएम)
बगोदर से विनोद सिंह (लेफ्ट)
भवनाथपुर सा भानु प्रताप शाही (बीजेपी)
डाल्टेनगंज से आलोक चौरसिया (बाजेपी)
जमुआ से केदार हाजरा (बीजेपी)
सिल्ली से सुदेश महतो (आजसू)
लोहरदगा से रामेश्वर उरांव (कांग्रेस)
छत्तरपुर से पुष्पा देवी (बीजेपी)
बड़कागांव से अंबा प्रसाद (कांग्रेस)
जगरनाथपुर से सोना राम सिंकू(कांग्रेस)
सिमडेगा से भूषण बारा(कांग्रेस)
रांची से सीपी सिंह (बीजेपी)
सारठ से रंधीर सिंह (बीजेपी)
बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम (जेएमएम)
निरसा से अप्रणासेनगुप्ता (बीजेपी)
चतरा से सत्यानंद भोक्ता (राजद)
रामगढ़ से ममती देवी (कांग्रेस)
मनोहरपुर से जोबा मांझी, (जेएमएम)
जामताड़ा से इरफान अंसारी (कांग्रेस)
पाकुड़ से आलमगीर आलम (कांग्रेस)
कांके से समरीलाल (बीजेपी)
टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो (जेएमएम)
गोड्डा से अमित मंडल (बीजेपी)
लिट्टीपाड़ा से दिनेश मरांडी (जेएमएम)
सिसई से जिग्गा सुसारन होरो (जेएमएम)
मंझगांव से निरल पूर्ति (जेएमएम)
जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता (कांग्रेस)
मांडर से बंधु तिर्की (झाविमो)
जामा से सीता सोरेन (झामुमो)
पोटका से संजीव सरदार(झामुमो)
जरमुंडी से बादल पत्रलेख(कांग्रेस)
पाकुड़ से आलमगीर आलम(कांग्रेस)
रामहल से अनंत ओझा (बीजेपी)
सरायकेला से चंपई सोरेन(झामुमो)
बोकारो से विरंची नारायण (बीजेपी)
हजारीबाग से मनीष जायसवा(बीजेपी)
चक्रधरपुर से सुखराम उरांव(झामुमो)
गिरिडीह से सुदिव्य कुमार(झामुमो)
बाघमारा से ढुल्लू महतो (बीजेपी)
बरही से उमाशंकर अकेला(कांग्रेस)
मनोहरपुर से जोबा मांझी(झामुमो)
कोडरमा से नीरा यादव (बीजेपी)
लातेहार से बैद्यनाथ राम(झामुमो)
महेशपुर से स्टीफन मरांडी(झामुमो)
खरसांवा से दशरथ गगरई(झामुमो)
विशुनपुर से चमरा लिंडा(झामुमो)
पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव (झाविमो)
महेशपुर से स्टीफन मरांडी(झामुमो)
ईचागढ़ से सविता महतो(झामुमो)
मधुपुर, हाजी हुसैन अंसारी(झामुमो)
मणिका, रामचंद्र सिंह(कांग्रेस)
मधुपुर से हाजीहुसैन अंसारी(झामुमो)
महगामा से दीपिका पांडेय सिंह(कांग्रेस)
बरकट्ठा से अमित यादव(निर्दलीय)
हटिया से नवीन जायसवाल(बीजेपी)
गांडेय से सरफराज अहमद(झामुमो)
सिमरिया से किशुन दास(बीजेपी)
नाला से रवींद्रनाथ महतो(जेएमएम)
देवघर से नरायण दास(बीजेपी)
राजधान्वर से बाबूलाल मरांडी(झाविमो)

अब आगे क्या?

ऐसा पहली बार हो रहा है कि झारखंड में चुनाव पूर्व बने किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। झारखंड में आज तक किसी पार्टी को अकेले बहुमत के लायक 41 सीटें नही मिली हैं। अब जब कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है तो राज्य को एक स्थिर और मजबूत सरकार मिला है। अब मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन को जल जंगल जमीन की रक्षा करनी होगी। झारखंड में 32 प्रतिशत वन भूमि है जिसे उजड़ने से बचाना होगा। खनिजों से समृद्ध झारखंड को विकास के मामले में भी समृद्ध बनाना होगा। पिछली सरकार के कई सद्प्रयास भी भ्रष्टाचार और अफसरशाही की भेंट चढ गये उसे ठिक करना होगा। और सबसे जरूरी कि आदिवासियों की जमीन बचाने का शोर तो यहां बहुत होता है लेकिन जमीन माफियाओं के कब्जे में जाती रही है उस पर अविलंब रोक लगाना होगा।

दोपहर तक मायूस थे कांग्रेस कार्यकर्ता

रांची में 23 दिसंबर को रिजल्ट को देखते हुये कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ खास उत्साहित नहीं थे। ज्यादतर मायूस या दम साधे चुपचाप रिजल्ट पर आंखें गड़ाये हुये थे। दोपहर तक महागठबंधन और भाजपा के बीच करीबी मुकाबला चल रहा था। साथ ही आजसू और झाविमो को मिला कर दस बारह सीटें आ रही थीं जिससे गणित भाजपा के पक्ष में दिख रहा था। लेकिन दोपहर के बाद भाजपा, झाविमो बुरी तरह से पिछड़ती चली गयी। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह लग रहा था कि भले भाजपा पीछे है, पर आजसू और जेवीएम उससे हाथ मिला लेंगे तो उनकी सरकार बन जायेगी। लेकिन एक बार आंकड़ा अपने पक्ष में देखते ही उनमें उत्साह भर गया।

रांची रेल मण्डल में रक्तदान शिविर

रांची : रांची रेल मण्डल में आज मेडिकल विभाग की ओर से मण्डल रेल अस्पताल में , रांची में रक्तदान शिविर लगाया गया। जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारीयों व कर्मचारियों ने भाग लिया । मण्डल रेल प्रबन्धक नीरज अंबष्ठ ने कहा कि ''आपके रक्तदान से लोगों की जान बच सकती है। यह बहुत बढ़िया का कार्य है। हमें वर्ष में कम से कम दो- तीन बार यह शिविर अवश्य लगाना चाहिए । अपर मण्डल रेल प्रबन्धक अजीत सिंह यादव ने कहा कि रक्त देने से स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं होती , बल्कि आप किसी का जीवन बचाते हैं।

सीसीएल को राष्ट्रीय सुरक्षा समारोह में चार पुरस्कार

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ''राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समारोह'' में उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड फॉर माईन्स का पुरस्कार वितरण किया। प्रतियोगिता में देश के सभी कोल माइन्स ने भाग लिया जिसमें सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) को खान सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चार राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड प्रदान किया गया। वर्ष 2015 में सीसीएल के आम्रपाली ओपेन कास्ट माइन्स को लोवेस्ट इंज्यूरी फ्रीक्वेंशी रेट प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर आउटपुट के लिए 'रनर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कांके विधानसभा समर के विजेता बने समरीलाल

रांची : भाजपा के खिलाफ जनादेश की आंधी में भी कांके विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार समरीलाल पर जनता ने भरोसा जताया और उन्हें चुन कर नये विधानसभा में भेजा है। चुनाव पूर्व भी ग्रीन रिवोल्ट ने समरीलाल का साक्षात्कार लिया था। जिसमें वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। समरीलाल की जीत का मुख्य कारण जनता से सीधा संवाद, उनका खुद बहुत ही जमीनी आदमी होना, बेदाग छवि और लंबे समय से क्षेत्र की जनता के बीच रह कर उनके सुख-दुख में साथ देना रहा। बड़े विधानसभा क्षेत्र कांके के किसानों से लेकर आमजनों को उनसे बहुत सारी उम्मीदे हैं। समरीलाल जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर 70 के दशक में राजनीति में आये। रिम्स के एक क्वार्टर में रहने वाले समरी लाल की सादगी और लोगों का साथ देना सभी उम्मीदवारों पर भरी पड़ा।

ठंड एवं पाला से बचाव में लो टनल प्लास्टिक तकनीक बेहद कारगर

संवाददाता

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी विभाग के वैज्ञानिक डॉ प्रमोद राय का कहना है कि जाड़े के मौसम में कम तापमान होने और पाला पड़ने पर होने वाले हानि से बचाव किया जाना संभव है। फसलों के पौधे के विकास में 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना जरूरी है। जाड़े के मौसम में मिटटी एवं हवा का तापमान रात के समय काफी कम हो जाता है। जिसके कारण स्वस्थ्य सब्जियों के पौधे को उगाना कठिन हो जाता है। विश्वविद्यालय ने लो टनल प्लास्टिक तकनीक विकसित किया है। यह तकनीक जाड़े के मौसम में कम तापमान और पाला से बचाव में लाभप्रद एवं मददगार साबित हो रहा है।

प्लास्टिक लो टनल एक छोटे प्रकार का गुफानुमा घर होता है। जिसके अंदर ग्रीनहाउस का प्रभाव दीखता है इसके कारण इस घर का तापमान बाहर की तुलना में ज्यादा होता है। कम ऊँचाई वाले इस गुफनुमा घर को विभिन्न आवरणों में 50 माइक्रोन की प्लास्टिक फिल्म, 40 मेस वाली कीड़ा रहित जाली और 35-50 प्रतिशत शेडनेट से निर्मित किया जाता है। गुफानुमा घर का निर्माण सरिया, बांस, एलडीपीई पाइप आदि से किया जा सकता है। जिसकी चौड़ाई 80 से। मी।, मध्य की ऊँचाई 40 से। मी। तथा दोनों सिरों को मिटटी में 5 से। मी। गहराई तक गाड़ते है। गुफानुमा घर को 50 माइक्रो मीटर युभीयुक्त प्लास्टिक से आच्छादित करके कम तापमान से होने वाले क्षति से बचा जा सकता है। इस निर्मित घर में विषाणुरहित स्वस्थ्य सब्जियों के पौधे या अगाती/बेमौसमी कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों एवं पत्तेदार सब्जियों आदि को सालों भर ....शेष पेज 3 पर

मणिपुर की कंगुजम ने विश्व को दिखाया आइना

ग्रेटा थनबर्ग की तरह ही इस नन्हीं कार्यकर्ता ने भी मैड्रिड में चल रहे 'कॉप- 25' सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से धरती, इंसानी नस्ल और उसके जैसे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए बिना देर किए कार्रवाई करने का आग्रह किया।

एजेंसियां: करीब ढाई महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में स्वीडन की एक सोलह साल की किशोरी ग्रेटा थनबर्ग ने जलवायु संकट पर अपनी तीखी राय जाहिर करते हुए पर्यावरण संरक्षण के मामले में महज औपचारिकता निभाने को लेकर दुनिया के तमाम देशों को कठघरे में खड़ा किया था। तब उनके सख्त तेवर की भी काफी चर्चा हुई थी। अब भारत में मणिपुर की आठ साल की नन्ही बच्ची लिसीप्रिया कंगुजम ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ग्रेटा थनबर्ग की तरह ही इस नन्हीं कार्यकर्ता ने भी मैड्रिड में चल रहे 'कॉप- 25' सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से धरती, इंसानी नस्ल और उसके जैसे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए बिना देर किए कार्रवाई करने का आग्रह किया।

कंगुजम अब तक इक्कीस देशों में जलवायु परिवर्तन की समस्या पर अपनी बात रख चुकी हैं और उन्हें दक्षिणी गोलार्ध की 'ग्रेटा थनबर्ग' बताया जा रहा है। पर्यावरणविदों के बीच यह खास आकर्षण का विषय है कि इतनी कम उम्र में यह बच्ची पारिस्थितिकी संतुलन के मसले पर कितना स-रोकार रखती है। लेकिन सच यह है कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति अपने आसपास की आबोहवा पर नजर रखता है और उसमें हो रहे बदलावों को करीब से महसूस कर पाता है तो यह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण बात है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में ग्रेटा थनबर्ग के साथ-साथ बारह देशों के पंद्रह अन्य युवा कार्यकर्ताओं ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने के लिए पांच देशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तब यह सवाल उठा था कि पिछले चार-पांच दशक से बढ़ते तापमान के मसले पर होने वाले वैश्विक सम्मेलनों में दुनिया भर के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि आखिर किस तरह की कार्य-योजना पेश करते हैं कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। क्या इसी रुख के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा? सवाल है कि पर्यावरणविदों की राय जब सामने आती है तब दुनिया भर में इस पर चिंता जताई जाती है, लेकिन जब उससे बचने के उपायों की बात आती है, तब खासतौर पर वे देश क्यों अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। जाहिर है, यह मुख्य रूप से व्यवस्था का सवाल और इच्छाशक्ति के अभाव का मामला है। इसलिए कंगुजम की यह बात महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि उसके जैसे नन्हे कार्यकर्ता व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन का संकट दूर होने का रास्ता अपने आप तैयार हो जाए। लेकिन वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक सवालों पर केंद्रित अमूमन हर साल होने वाले सम्मेलनों के बावजूद हालत आखिर ऐसी क्यों है कि हर अगले वर्ष जलवायु के सामने खड़ी चुनौतियां गहरी होती जा रही हैं? दुनिया के जो देश कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ में आ रही है और इस मसले पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का दबाव क्यों नहीं काम कर पा रहा है?

आखिर क्यों ऐसी नौबत आई है कि अब नई पीढ़ी के कम उम्र के बच्चों की भी नजर इस समस्या पर जा रही है और वे न केवल खुद अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल, पहले ग्रेटा थनबर्ग और अब लिसीप्रिया कंगुजम जैसी किशोर और युवा कार्यकर्ताओं ने अब तक के वैश्विक पहलकदमियों को कठघरे में खड़ा किया है कि क्या केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताने भर से पर्यावरण की गंभीर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा!

जरूरत से ज्यादा नमक और वसा मिला रही है कंपनियां

सीएसई लैब रिपोर्ट पर जवाब देने से बच रही हैं कंपनियां

एफएसएसएआई ने 100 ग्राम के चिप्स, नमकीन और नूडल्स में 0.25 ग्राम सोडियम की मात्रा निर्धारित की है। जबकि 100 ग्राम के सूप और फास्ट फूड के लिए 0.35 ग्राम सोडियम की सीमा निर्धारित की है। नोर क्लासिक थिक टोमेटो सूप में निर्धारित सीमा से 12 गुणा अधिक नमक पाया गया है। हल्दीराम के नट क्रेकर में भी आठ गुणा अधिक नमक मिला है। 100 ग्राम के चिप्स और नमकीन के लिए वसा की सीमा आठ ग्राम निर्धारित है लेकिन अधिकांश चिप्स और नमकीन में यह 2-6 गुणा अधिक पाया गया है। मैकडोनल्ड्स के बिग स्पाइसी पनीर रैप, सबवे के पनीर टिक्का सैंडविच (6 इंच) और केएफसी हॉट विंग्स के चार पीस में दोगुना से अधिक वसा मिला है। 2019 का ड्राफ्ट फास्ट फूड में 25 प्रतिशत विचलन की बात कहता है लेकिन यह मात्रा उससे बहुत अधिक है। यही वजह है कि फूड इंडस्ट्री आप तक जानकारी नहीं पहुंचने देना चाहती। और यही वजह है कि इंडस्ट्री ड्राफ्ट को लागू करने का विरोध कर रही है। उसकी रणनीति स्पष्ट है। वह चाहती है नई समिति बने और नियमों को और कमजोर कर दिया जाए। सेसिकरण की अध्यक्षता में 2018 में बनी कमेटी की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन इस कमेटी ने उद्योगों के हितों को ध्यान रखा है।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

नयी सरकार से उम्मीदें

झारखंड में विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद एक निर्वाचित और मजबूत सरकार आ चुकी है। अब अगर मगर और समर्थन देने लेने या कमजोर गठबंधन वाली सरकार के संभावनाओं का पटाक्षेप हो चुका है। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो की सरकार सदैव से जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने का वादा करते रही है। पहली बार झामुमो को खुल कर रचनात्मक काम करने का मौका मिला है। इसके पहले कमजोर सरकारों का मुखिया होने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब भी मौका मिला वह रचनात्मक कामों पर संभवतः ध्यान नहीं दे पाये होंगे !अब वैसी कोई बाधा नहीं है। ऐसे में झारखंड जैसा राज्य जो विश्व भर में प्राकृतिक संपदाओं से सबसे परिपूर्ण राज्य है उसके विकास में अब कोई रूकावट नहीं होनी चाहिये। यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहां कोई भी सरकार जनता की उम्मीदों आकाक्षाओं पर खड़ी नहीं उतरी। दलील दी जाती है कि यह युवा राज्य है लेकिन राज्य बने तकरीबन दो दशक हो चुके हैं जो झारखंड जैसे छोटे और प्रत्येक लिहाज से परिपूर्ण राज्य के विकसित होने के लिये पर्याप्त थे।

झारखंड राजनीतिक अस्थिरता, नक्सलवाद, पलायन से ग्रस्त रहा है। अफसोस कि यहां पर्यावरण का संरक्षण कभी मुद्दा नहीं रहा। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड में 32 प्रतिशत भूभाग पर वन हैं इस कारण से यहां गंभीर पर्यावरणीय संकट देखने को नहीं मिला लेकिन हमारी नदियां प्रदूषित हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को पीने के लिये शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हैं। कई क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था सही नहीं है। राज्य की कृषि आज भी तकरीबन एकफसली ही है। राज्य में व्यावसायिक खेती को भी बढावा देने की जरूरत है।

राजधानी में पर्यावरण के नियमों को ताक पर रख कर तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, गर्मियों में पेयजल से दो चार होने वाली राजधानी के लिये यह एक अलग ही संकट है। ऐसे में नयी सरकार से यह उम्मीद है कि वह राज्य के पर्यावरण , कृषि, जल, जंगल को भी प्राथमिकता में रखेगी?

ग्रीन लैंड , नदियों, तालाबों के कैचमेंट से लेकर आदिवासियों की जमीन को बचाने का वादा तो सभी सरकारें करती रहीं पर राजधानी में ही एक-एक कर ,ऐसे बहुत सारे भूभागों पर आवास और व्यावसायिक निर्माण होते रहे। ये सवाल जनता के मन में भी उठता है कि आखिर किसी ओपने स्पेस, ग्रीनस्पेस, नदियों तालाबों के ग्रीनलैंड में आखिर कौन लोग निर्माण कर रहे हैं ? और कानून तब कहां चला जाता है। रांची में ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें किसी भूखंड पर निर्माण गैरकानूनी बताया गया, शोर होते रहा उसके बाद सलीके से वहां बड़े निर्माण होने लगे प्लॉटिंग हो गयी और वह ग्रीनलैंड, सरकारी जमीन या नदियों तालाबों के कैचमेंट कंक्रीट से पट गये। नयी सरकार को इस पर ध्यान देना होगा।

कूड़ा देने पर मिलेंगे पैसे

एजेंसियां

फिलहाल देश में ऐसी व्यवस्था है कि घर या संस्थान से कचरा उठवाने पर पैसे देने पड़ते हैं लेकिन अब एक नई व्यवस्था शुरू हुई है। इसके तहत अब कचरा उठवाने पर पैसे देने नहीं पड़ेंगे बल्कि जो भी व्यक्ति अथवा संस्थान कचरा देगा उसे उसके पैसे मिलेंगे। जी.. हां.. पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी पहल के तहत गुजरात में अहमदाबाद आधारित एक कंपनी ने होटलों, अस्पतालों तथा बड़े पैमाने पर जैविक रूप से परिवर्तनीय गीले कचरे पैदा करने वाले ऐसे अन्य संस्थानों अथवा संगठित रिहायशी इलाकों से कचरा लेकर जैविक खाद बनाने तथा इसकी बिक्री से होने वाले लाभ को कचरा देने वाले संस्थानों के साथ साझा करने वाला राज्य का इकलौता संयंत्र शुरू किया है। जैविक कचरा प्रबंधन तथा पर्यावरणीय समाधान प्रदाता कंपनी एन्वीकेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विवेक पटेल ने यहां यूएनआई को बताया कि फिलहाल प्रतिदिन 40 टन अथवा 40 हजार किलो गीले बायो डिग्रेडेबल कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता वाल यह संयंत्र अहमदाबाद के निकट च्वजोल में दो दिन पहले ही शुरू किया गया है। 40 टन कचरे से 16 टन जैविक खाद प्रति दिन बन सकता है। इसकी बिक्री से होने वाले लाभ का उपलब्ध कराए गए कचरे की मात्रा के हिसाब से आंकलन कर 33 प्रतिशत उन संस्थानों को दिया जाएगा जिन्होंने कचरा उपलब्ध कराया है।कचरा एकत्र करने वाली कंपनी ग्रीन्सवीकीप सोल्यूशन्स के भी निदेशक पटेल ने कहा कि कंपनी ऐसे किसी भी संस्थान से कचरा एकत्र कर सकती है जिसके पास से प्रति दिन उक्त श्रेणी का कम से कम 20 किलो कचरा होता हो।

जलवायु परिवर्तन की दर दुरुस्त करने की पहल

सुनीता नारायण

जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का एक और दौर मैड्रिड में संपन्न हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-25) कुछ मामलों में अलग है। इस बार लगभग आम-सहमति बनी है कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में हो रहा है। अब हर कोई यह मानता है कि इस दिशा में काम करने का वक्त हो गया है। अब और हीलाहवाली नहीं चलेगी। तथ्य यह है कि मैड्रिड में कदमों को गलत ठहराने या नाममात्र एवं सस्ते कदम उठाने के तरीके तलाशने को लेकर नए खेल खेले गए। सीओपी-25 सम्मेलन में विश्वसनीय बाजार प्रणाली के विकास को लेकर काफी चर्चा हुई। देशों को कार्बन-तटस्थ या विशुद्ध रूप से शून्य-कार्बन वाला बनाने के लिए ऐसी बाजार प्रणालियां बेहद जरूरी हैं।

यह सब सुनने में काफी अच्छा और बड़ा लग रहा है। लेकिन कहते हैं न कि प्याले से मुंह तक पहुंचने में बहुत कुछ हो सकता है। जलवायु संबंधी वार्ताओं में मैंने यह पाया है कि अक्सर सराहनीय विचार पेचीदा बहसों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। असल में यह रोजमर्रा का काम है। इसका पता आपको तब चलता है जब गुबार थम चुका होता है। मसलन, वर्ष 2015 में पेरिस में संपन्न सीओपी-21 की घटनाओं को लीजिए। उस समय मनोदशा उत्साह से भरपूर थी क्योंकि एक नया समझौता हुआ था। सभी देशों ने उत्सर्जन में कटौती संबंधी प्रतिबद्धता पर सहमति जताई थी। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) कहे जाने वाले इन लक्ष्यों तक काफी चर्चा के बाद पहुंचा जा सका था। यह भी तय किया गया था कि एनडीसी का मकसद धरती का तापमान पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के खतरनाक स्तर से नीचे ही रखना है। लेकिन अब पेरिस की 'सफलता' के भेद खुल रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि अगर सभी देश एनडीसी में दर्ज कदमों पर चलते हैं तो वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। इतना ही नहीं, देश खासकर कार्बन बजट का बेजा इस्तेमाल कर चुके अमीर देश उतना भी नहीं कर रहे हैं जिनके लिए वे हामी भर चुके हैं। मसलन, जर्मनी स्थित संगठन क्लाइमेट ट्रैकर के मुताबिक, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के कदम 4 डिग्री सेल्सियस, चीन एवं जापान के कदम 3-4 डिग्री सेल्सियस और यूरोपीय संघ के भी कदम 2-3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का सबब बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर सभी देशों ने उत्सर्जन के इसी स्तर का अनुसरण किया तो इस सदी के अंत तक तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब हकीकत पर लौटते हैं। ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और ऐसा तब हो रहा है जब करोड़ों लोगों को बुनियादी ऊर्जा सुरक्षा मिलने का अब भी इंतजार है।

इस हकीकत के बीच विशुद्ध शून्य कार्बन का विचार सुनने में काफी अच्छा लगता है। इसका यह मतलब है कि देश अपने लक्ष्य से नीचे रह जाएंगे। यानी वे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते रहेंगे लेकिन वे कार्बन के अवशोषण या निपटाने के तरीके निकालेंगे ताकि उनके बही-खाते में उत्सर्जन शुद्ध-शून्य नजर आए। लिहाजा इस कार्बन का अवशोषण कैसे काम करता है? एक, उत्सर्जन योग पेड़ों में मौजूद कार्बन डाई-ऑक्साइड की गणना करेगा कि कितना उत्सर्जन हुआ और कितना अवशोषित हुआ।

फिर ऐसी नई तकनीकें भी हैं जो वातावरण से कई टन कार्बन डाई-ऑक्साइड सोखने और उसे जमीन के भीतर दफनाने का काम करेंगी। इसका यह मतलब होगा कि देश अब न केवल उत्सर्जन में कटौती करने बल्कि प्रसार जारी रखने और फिर सबकी सफाई की योजना बना सकता है। वे दूसरे देशों में कार्बन-अनुकूल परियोजनाओं में निवेश कर क्रेडिट भी खरीद सकते हैं और उसे अपने बही-खाते में उसे जोड़ सकते हैं। यहां पर बाजारों को लेकर चर्चा भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यह भी एक तथ्य है कि अफ्रीका या एशिया के सुदूर गांवों में पेड़ लगाना यूरोप या जापान में पेड़ लगाने से कहीं अधिक सस्ता है। हमारी दुनिया में अब भी उत्सर्जन कटौती के सस्ते विकल्प मौजूद हैं। लिहाजा बाजारों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि कार्बन धमक एवं क्रेडिट के लिए विकासशील देशों में निवेश किया जा सकता है। इन जलवायु परिदृश्यों में काम कर चुके हम जैसे अधिकतर लोगों के लिए ये शब्दावलियां जानी-पहचानी हैं। वर्ष 1997 के क्योटो समझौते में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकासशील देशों में तकनीकी संक्रमण के लिए भुगतान करने के ऐसे ही विचार से शुरू हुआ था लेकिन जल्द ही यह सस्ता एवं पेचीदा होते हुए भ्रष्ट विकास व्यवस्था में तब्दील होता चला गया।

पेरिस समझौते के बाद इस बार सभी देशों को घरेलू स्तर पर उत्सर्जन कटौती करनी है। इसलिए अगर भारत अपना सस्ता उत्सर्जन कटौती विकल्प किसी अमीर देश को बेच देता है तो वह उस कटौती स्तर को कैसे हासिल कर पाएगा जिसकी जरूरत इस दुनिया को है? याद रखें कि अमीर एवं गरीब दोनों के लिए ही यह एक बड़ा संकट है क्योंकि तापमान वृद्धि का असर सब पर एक जैसा होगा। सवाल है कि क्या किया जाना चाहिए? शुद्ध-शून्य लक्ष्य तय करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य देशों को घरेलू स्तर पर अधिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना और फिर जो कुछ भी बचा हुआ है उसे वैश्विक लेनदेन प्रणालियों के जरिये खरीदने का होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कार्बन बिक्री पर एक आधार मूल्य तय करना है, इस दर से नीचे परियोजनाएं योग्य नहीं हो पाएंगी।

इसका यह मतलब होगा कि विकासशील देशों में केवल उन्हीं परियोजनाओं को फंड मिलेगा जो कायापलट करने वाली हैं। भारत जैसा देश अधिक स्वच्छ भविष्य की तरफ छलांग लगा सकता है। हम पहले प्रदूषण फैलाने और फिर उसकी साफ-सफाई से बच सकते हैं। हम इसी भविष्य की चाह रखते हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए जलवायु समझौतों के शब्दों पर अमल करना होगा, केवल बात करने से काम नहीं चलेगा।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं)

बड़े वैश्विक अशांति का कारण बन रहा है जल

मुरलीधर

ज्यादातर प्रचार यही है कि अंतरराष्ट्रीय उजाड़ का कारण आतंकवाद, सांप्रदायिक विभेद, सीमा-विवाद अथवा आर्थिक तनातनी है। बढ़ती हवस, बढ़ता उपभोग, घटते प्राकृतिक संसाधन और दूसरे के संसाधन पर कब्जे की नीयत ने ये हालात पैदा किए हैं। इन संसाधनों में पानी सबसे प्रमुख है। यकीन न हो तो दुनिया के मानचित्र पर निगाह डालिए। पानी की कमी ने कुछ ऐसे हालात पैदा किये हैं कि हमारा विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है।

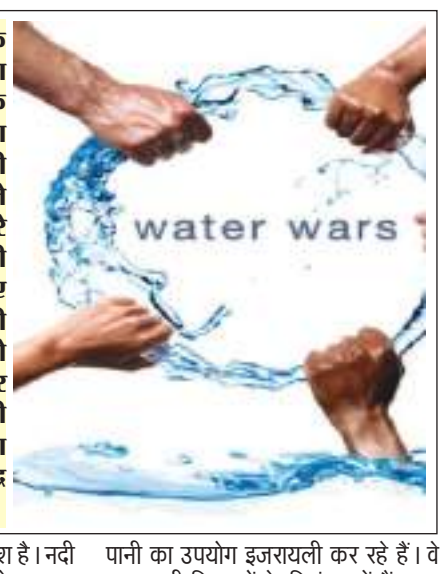

हम इक्कीसवीं सदी के इस दूसरे दशक के अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस वक्त की दो सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं- हताशा और तनाव। संयुक्त राष्ट्र चिंतित है कि लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं। उसकी चिंता यह भी है कि लोग एक देश से उजड़ कर दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं। यूरोपीय शहरों के मेयर चिंतित हैं कि विस्थापित उनके यहां आकर क्यों बस रहे हैं। जिन इलाकों में वे जाकर बस रहे हैं, वहां कानून-व्यवस्था की समस्याएं खड़ी हो रही हैं।

इन समस्याओं और चिंताओं में तीसरे विश्व युद्ध के बीज मौजूद हैं। ज्यादातर प्रचार यही है कि इस अंतरराष्ट्रीय उजाड़ का कारण आतंकवाद, सांप्रदायिक विभेद, सीमा-विवाद अथवा आर्थिक तनातनी है। किंतु सच यह नहीं है। आज तुर्की-सीरिया-इराक विवाद ने शिया-सुन्नी और आतंकवादी त्रासदी का रूप भले ही ले लिया हो, किंतु वास्तविकता यही है कि विवाद की शुरुआत इफरेटिस नदी के पानी को लेकर ही हुई थी। इफरेटिस नदी, तुर्की से निकल कर सीरिया होते हुए इराक तक जाती है। तुर्की का दावा है कि इस नदी में आने वाले कुल पानी में साढ़े अट्ठासी प्रतिशत योगदान तो अकेले उसका ही है, फिर भी वह तो मात्र तियालीस प्रतिशत पानी ही मांग रहा है। दूसरा पक्ष देखिए। इफरेटिस के प्रवाह में सीरिया का योगदान 11.3 प्रतिशत और इराक का शून्य है, जबकि पानी की कमी वाले देश होने के कारण सीरिया, इफरेटिस के पानी में बाईस प्रतिशत और इराक तियालीस प्रतिशत हिस्सेदारी चाहता है।

वस्तुस्थिति यह है कि तुर्की ने मूल नदी जल बंटवारा संधि (1987) का उल्लंघन करते हुए 15 अप्रैल, 2014 के बाद से इफरेटिस नदी के प्रवाह में कटौती करनी शुरु की और अपनी दादागीरी जारी रखते हुए 16 मई, 2014 को सीरिया और इराक के हिस्से का पानी छोड़ना पूरी तरह बंद कर दिया। परिणामस्वरूप, नदी किनारे की खेती योग्य भूमि रेगिस्तान में तब्दील होती गई। सीरिया दुनिया में सबसे पुरानी खेती का देश है। नदी जल विवाद ने ऐसे देश के एक बड़े भू-भाग में खेती कार्य को दुष्कर बना दिया। इससे करीब बीस लाख की आबादी उजड़ी। उजड़ने वाले बगदाद गए, लेबनान गए, फिर यूरोप के देशों तक पहुंचे। आज सीरिया में पानी का संकट इतना गहरा है कि सीरिया की करीब सत्तर प्रतिशत आबादी पीने के पानी की कमी से जूझ रही है।

यदि हम इफरेटिस नदी में 17.3 अरब क्यूबिक मीटर जल की उपलब्धता आंकड़े देखें तो समझ में आता है कि संबंधित तीनों देशों में पानी की मांग ज्यादा है और इफरेटिस नदी में पानी कम है। इसलिए मांग-आपूर्ति के इस असंतुलन के कारण भी तीनों देशों के भीतर तनाव बढ़ना ही था। तुर्की और इराक के लोगों द्वारा सीरिया के विस्थापितों के घरों और जमीनों पर कब्जे की हवस ने पूरा माहौल ही तनाव और हिंसा से भर दिया। अब कोई तुर्की से पूछे कि सीरिया और इराक में विस्थापन की बुनियाद किसने रखी? तुर्की द्वारा इफरेटिस और टिगिरिस पर बांधों ने ही तो। दूसरा उदाहरण फिलस्तीन है। फिलस्तीन के पश्चिमी तट के साझे स्रोतों के 85प्रतिशत पानी का उपयोग इजरायली कर रहे हैं। वे इजरायली किबुत्जों के नियंत्रण में हैं। एक ओर फिलस्तीन में बाहर से आकर बसे इजरायलियों के पास बड़े-बड़े खेत हैं, बागान हैं, स्वीमिंग पूल हैं। इजरायलियों के पास सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी है, दोहन के लिए मशीने हैं तो दूसरी ओर ग्रामीण फिलस्तीनियों को बहता पानी तक नसीब तक नहीं है। वे जो पानी पी रहे हैं, वह जहरीला है। इसलिए ज्यादातर लोग किडनी में पथरी जैसी बीमारियों के शिकार हैं। फिलस्तीनियों के पास जमीने हैं, लेकिन वे इतनी सूखी हैं कि वे उनमें कम पानी की फसलें भी नहीं उगा सकते। यही वजह है कि एक आम फिलस्तीनी, एक दुखी खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मध्य एशिया और अफ्रीका के करीब चालीस देशों में कायम सामुदायिक अस्थितरता का मूल कारण पानी ही है। जॉर्डन, केन्या, यूथोपिया, सोमालिया, सूडान, ब्राजील सब जगह एक जैसे हालात हैं। समय बीतने के साथ-साथ यह समस्या और गंभीर होती जा रही है और दुनिया को हिंसा और युद्ध के जिस रणक्षेत्र की ओर ले जा रही हैं, क्या यह पानी की खातिर विश्व युद्ध का कुरुक्षेत्र नहीं है? सवाल है कि क्या भारत इससे अछूता है? इस साल मार्च में दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में पानी के झगड़े में एक की हत्या कर दी गई थी। पानी की आपूर्ति में कमी और बिल में बढ़ोत्तरी के विरोध जयपुरवासी सड़क पर उतरे। शिमलावासियों के नलों में तीसरे दिन आते पानी का आक्रोश, स्वयं हिमाचल के महामहिम राज्यपाल के मन में दिखा। उत्तराखंड के बानवे में से इकहत्तर नगरों-कस्बों में मानक से बहुत कम और खराब पानी मिला। पानी से जुड़ी कई समस्याएं भारत के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विवाद का कारण बनती जा रही हैं। सतलुज नदी बंटवारे के कारण हरियाणा-पंजाब के बीच तलवारें खिंचती रहती हैं। कावेरी जल विवाद का आक्रोश हमने बीते मार्च-अप्रैल के दौरान संसद में भी देखा और सड़कों पर भी। मानसरोवर स्थित मूल स्रोत से निकलने वाली सिंधु नदी के लद्दाख क्षेत्र में कब्जे की चीनी साजिशों से हम वाकिफ हैं ही। भारत आने वाले तिब्बती प्रवाहों में चीन द्वारा परमाणु कचरा डालने और बांध बना कर पानी रोकने की करतूतें पुरानी हैं। जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद हैं। नेपाल मूल की नदियों में नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से भारत में होने वाली तबाही को लेकर हम चिंतित रहते ही हैं।

दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अशांति पानी से उपजी है तो शांति का मार्ग भी पानी में ही तलाशना चाहिए। किंतु भारत के पानी संकट का समाधान, इजरायली के जल प्रबंधन का मॉडल नहीं हो सकता। भारत का जल प्रबंधन दूसरे के संसाधन की ओर ताकने की बजाय अपने पास जो है, उसी से जीवन चलाने वाला होकर ही शांतिप्रद हो सकता है। पानी के उपयोग के मामले में हमें अनुशासित होना पड़ेगा, जल अपव्यय की आदत छोड़नी होगी। कम पानी और वर्षा आधारित खेती-बागवानी को अपनाना चाहिए। जितना पानी कुदरत से लें, उसे वैसा और उतना पानी संचित करके लौटाना चाहिए।

रोड एक्सीडेंट में गर्भवती बाघिन की मौत

कार्बेट टाइगर रिजर्व के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में एक गर्भवती बाघिन की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाघिन दो से तीन महीने में तीन शिशुओं को जन्म देने वाली थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में इसकी तस्दीक हो गई है। यही नहीं, पिछले एक हफ्ते में राज्य में चार गुलदार सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। वन्यजीवों को संरक्षण देने के लिहाज से राज्य की स्थिति बेहतर है। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे वन्यजीव विकास की कीमत चुका रहे हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागड़ी बताते हैं कि शुक्रवार सुबह 8 बजे के आसपास खबर मिली कि स्टेट हाईवे पर चूनाखान क्षेत्र के पास एक बाघिन सड़क पर मृत पड़ी है। घटनास्थल पर कार की कांच के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। उनका कहना है कि गाड़ी तेज़ रफ्तार में रही होगी, जिससे ज़ोरदार टक्कर लगी। ऐसा भी संभव है कि कोहरा होने की वजह से वाहन चालक को कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। हालांकि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी से वाहन की पहचान की कोशिश की जा रही है। डीएफओ ने बताया कि पोस्टमार्टम में सड़क दुर्घटना में मौत की पुष्टि हुई है, साथ ही बाघिन के तीन भ्रूण भी मिले हैं। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव भरतरी कहते हैं कि बाघ-हाथी बहुल्य क्षेत्र में वाहन चलाते समय लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जाती है। लोगों को जागरुक करने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जंक फूड से है सबसे ज्यादा बीमारी का खतरा

क्लासिक नट क्रैकर्स पैकेट को खोलने या रेगुलर नॉन वेज सुप्रीम पिज्जा खाने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। सिर्फ 35 ग्राम नट क्रैकर्स चट करते ही आप रोज के तय मानक का करीब 35 फीसदी नमक और 26 फीसदी वसा का उपभोग कर चुके होंगे। और यदि चीज से लबरेज पिज्जा के चार बराबर टुकड़े खा लिए हैं तो समझिए कि आपने एक दिन की जरूरत भर का 99.9 फीसदी नमक व 72.8 फीसदी वसा खा लिया है। ज्यादा नमक, ज्यादा वसा (फैट), ट्रांस फैट और कार्बोहाइड्रेट वाले इस तरह के जंक फूड का उपभोग काफी घातक नतीजे वाला हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि यहमधुमेह, उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारी और कैंसर तक को खुला न्यौता देने जैसा है।

उत्तराखंड:कैंपा फंड से सहेजी जाएंगी ऑर्किड की प्रजातियां

एजेंसियां:उत्तराखंड के समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में ऑर्किड की कुल 236 प्रजातियां चिन्हित की गई हैं। अलग-अलग अध्ययन में यह भी पाया गया है कि राज्य में ऑर्किड फूलों के लिए अच्छा पर्यावरणीय माहौल है। फूलों की दुनिया में ऑर्किड की अलग अहमियत है। ज्यादातर हिमालयी राज्यों में पाए जाने वाले ऑर्किड फूल अपने रंग, खास बनावट और जटिल पुष्प संचरना के चलते बेहद दिलकश माने जाते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और फूलों में दिलचस्पी रखते हैं तो उत्तराखंड का ''प्रोजेक्ट ऑर्किड'' आपको आकर्षित करेगा। उत्तराखंड वन विभाग ने कैंपा योजना (कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) के तहत ऑर्किड की अलग-अलग प्रजातियों को सहेजने के लिए प्रोजेक्ट ऑर्किड शुरू किया है। उत्तराखंड वन

विभाग के वन संरक्षक (अनुसंधान) संजीव चतुर्वेदी बताते हैं कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यावरण के लिहाज से अहम ऑर्किड की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वास में सहेजना है। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ के गोरी घाटी क्षेत्र के लुमती वन पंचायत में ऑर्किड के फूल लगने शुरू हो गए हैं। यहां 4.25 हेक्टेअर क्षेत्र में ऑर्किड की 36 प्रजातियां सहेजी गई हैं। गोरी घाटी क्षेत्र के अंदर और आसपास के इलाकों में शोधकर्ताओं ने वर्ष 2019 तक ऑर्किड की 127 प्रजातियां चिन्हित की हैं।

ऑर्किड धरती के साथ पत्थर, पेड़ या झाड़ियों पर भी पनप जाता है। राज्य के समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में ऑर्किड की कुल 236 प्रजातियां चिन्हित की गई हैं। अलग-अलग अध्ययन में यह भी पाया गया है कि राज्य में ऑर्किड फूलों के लिए अच्छा पर्यावरणीय माहौल है। गोरी घाटी क्षेत्र को हम इनका पसंदीदा घर भी कह सकते हैं। लुमती के अलावा चमोली के मंडल गांव और नैनीताल में भी ऑर्किड को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। चमोली के गोपेश्वर में मंडल से तुंगनाथ के बीच ऑर्किड की 67 प्रजातियां सहेजी गई हैं। यहां का कुंड-कालीमठ क्षेत्र ऑर्किड का हॉट स्पॉट माना जाता है। 67 में से 17 प्रजातियां अपने औषधीय गुणों के लिहाज से स्थानीय लोगों के बीच बेहद अहम मानी चाती हैं। साज-सज्जा के साथ इसके औषधीय गुणों के चलते स्थानीय लोग भोजन से लेकर दवाओं तक इसका इस्तेमाल करते हैं।

इसी वर्ष जुलाई में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑर्किड फूलों को लेकर अपनी पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। जिसमें बताया गया कि देश में 1,256 ऑर्किड की प्रजातियां हैं। जिनमें से 388 प्रजातियां खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। ऑर्किड फूलों के लिए सबसे ज्यादा समृद्ध अरुणाचल प्रदेश हैं, जहां इसकी 612 किस्मों के फूलों मिलेंगे। इसके बाद सिक्किम 560 अलग-अलग किस्म के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग में ऑर्किड की 479 प्रजातियां पायी गईं।

समूचे ऑर्किड परिवार को कनवेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पिसीज़ ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लॉरा के तहत अपेंडिक्स-2 में शामिल किया गया है। यानी इन पर फिलहाल कोई पर्यावरणीय खतरा नहीं है लेकिन इस्की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनके व्यापार पर वैश्विक प्रतिबंध लागू है।

बेड पर खाने की है आदत तो हो जाइए सावधान

दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर चिप्स खाते हुए नेटफ्लिक्स देखने से बेहतर क्या हो सकता है। बेड पर खाना कई स्थितियों में सहज मालूम होता है लेकिन यह कई मायनों में आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

रूम में टीवी नहीं भी देखते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लैपटॉप या फोन पर नेटफ्लिक्स जरूर देखते होंगे। दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर चिप्स खाते हुए नेटफ्लिक्स देखने से बेहतर क्या हो सकता है। बेड पर खाना कई स्थितियों में सहज मालूम होता है विशेषकर जब आप थके हुए होते हैं या फिर आपको आलस आ रहा होता है लेकिन यह कई मायनों में आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कभी-कभार बिस्तर पर नाश्ता मजेदार हो सकता है लेकिन इस-ाकी आदत बना लेना अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको ऐसे चार कारण बताने जा रहे हैं, जिन्हें जान लेने के बाद आपको अगली बार से बेड पर खाना खाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है।

आपकी नींद हो सकती है प्रभावित

जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसी बिस्तर पर खाना खाने से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। अगर आप बिस्तर पर बैठे-बैठे टीवी देखते-देखते खाना खाने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं तो इससे आपके दिमाग को लगेगा कि बिस्तर सोने के लिए एक शांत जगह नहीं है। बिस्तर पर खाना खाने से आपकी नींद प्रभावित होती है क्योंकि ऐसा करने से आपका मन बैचेन रहता है।

बिस्तर पर खाना खाने से रोगाणु और बैक्टीरिया पनपते हैं

अपनी चादरों को साफ रखना उतना आसान नहीं है, जितना उन्हें समझा जाता है विशेषकर जब आप रोजाना उस पर बैठ कर खाना खाते हों। ऐसा करने से आपका बेड रोगाणु और बैक्टीरिया के लिए संभावित रूप से एक प्रजनन केंद्र बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर अंतराल पर अपनी बिस्तर की चादरें बदलनी चाहिए ताकि आपकी नींद खराब न हो।

भटक सकते हैं आप

बिस्तर पर खाना खाने से आपका ध्यान भटक सकता है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा ध्यान भटका हुआ होता है तो हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। जब आप आरामदायक कंबल के अंदर नेटफ्लिक्स देखते हुए नूडल्स खा रहे होते हैं तो हम अपने शरीर की भी नहीं सुनते हैं। ऐसा करने से हम हर प्रकार के नियंत्रण को भूल जाते हैं।

बिस्तर पर भोजन करने से चीटियां व कॉकरेच आकर्षित हो सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा भी आपकी चादर पर चीटियों की लाइन लगा सकता है। चीटियों के काटने से शरीर पर लाल रंग के निशान हो सकते हैं, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे।अगर आपको चोट या आप बीमार न हों तो आपको बिस्तर पर खाना खाने से बचना चाहिए। इसके बजाए आप डाइनिंग टेबल और जमीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं।

इकोस्मार्ट बनेगा हटिया स्टेशन

संवाददाता

रांची : हटिया स्टेशन को इको स्मार्ट स्टेशन बनाये जाने को लेकर एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मण्डल रेल प्रबन्धक इन्फ्रा अजीत सिंह यादव ने की। उन्होंने कहा कि देशभर में कुल 37 स्टेशनों को प्रथम चरण में इको फ्रेंडली स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनी थी और इसमें रांची मण्डल के रांची स्टेशन के साथ- साथ हटिया स्टेशन को भी इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि यात्रियों की भागीदारी के बिना यह कार्य संभव नहीं है। यात्रियों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए स्टेशनों पर उद्घोषणा की जा रही हैं नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं स्टेशनों पर स्लोगन व चित्रकारी की जा रही है। पर्यावरण को बचाना और उसे प्रदूषित होने से रोकना आज सबसे महत्वपूर्ण हो गया है हवा, जल जैसी जीवन उपयोगी चीजें लगातार दूषित होती जा रही हैं। सभी विभागों को मिलजुल कर काम करने की और संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक अवनीश ने कहा कि ''हटिया स्टेशन को इको स्मार्ट बनाने के लिए हम सभी को मिलजुलकर प्रयास करना होगा। स्टेशन पर नियुक्त सभी विभागों के कर्मचारियों को मिल-जुलकर कार्य करना होगा।

हटिया स्टेशन को इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन प्लेटफार्म संख्या 01 पर स्थापित की गई है। साफ-सफाई हेतु यंत्रीकृत सफाई अनुबंध किया गया है। स्वछता एवं सफाई की देख रेख के लिए तथा अपराध पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।प्रकाश व्यवस्था हेतु एलईडी लाइट की व्यवस्था की गई है।

प्रकृति से जुड़ी चित्रकारी स्टेशन एवं स्टेशन परिसर में की गई है। उचित जल प्रबंधन हेतु स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वाटर ऑडिट करवाया गया है। स्टेशन परिसर में वायो डिग्रेडिबल एवं वायो नॉन डिग्रेडिबल कचरे को अलग अलग संग्रहण एवं निपटान की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हटिया स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण , ग्रीन कवर में वृद्धि की गई है। विद्युत उपभोग में कुशलता के लिए एनेरजी ऑडिट स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करवाया गया है। वाटर रिसाइकिल प्लांट स्थापित किया जा चुका है। वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को अप्रैल 2020 तक स्थापित करने की योजना है। सभी टॉइलेट को बायो टॉइलेट के रूप में विकसित किया जा रहा है।

हटिया स्टेशन को 1एसओ 14001 प्रदान किया गया है। मण्डल सांस्कृतिक संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर एक नुक्कड़ नाटक भी किया। इस मौके पर वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त महेश्वर सिंह , वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक अवनीश , वरिष्ठ मण्डल अभियंता अमित कंचन, मण्डल अभियंता अजय कुमार , सहायक यांत्रिक अभियंता रीतिका रश्मि , सहायक मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक सी उरांव, यातायात निरीक्षक , जी आर पी, आरपीएफ, स्टेशन मास्टर, स्वास्थ्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक तथा सभी विभागों के अभियंता उपस्थित थे।

ठंड एवं पाला से बचायेगा लो टनल

.....पेज 1 का शेष मौसम को अनुकूल करके उगाया जा सकता है। इसके उपयोग से मिटटी का तापमान, हवा का तापमान , प्रकाश की तीव्रता व हवा की आद्रता आदि को नियंत्रित किया जा सकता है।

इस घर की सहायता से कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों (लौकी, तरबूज, खीरा, खरबूजा आदि) के पौधे की क्यारी या प्लास्टिक प्रो झ ट्रे में दिसम्बर झ जनवरी में उगाकर अगाती/बेमौसमी सब्जियों की खेती सफलता से की जा सकती है। प्लास्टिक प्रो झ ट्रे में में सामान्यतः केंचुआ खाद एवं कोकोपीट का बराबर मात्र में प्रयोग किया जाता है ।टपक (ड्रिप) सिंचाई,उर्वरीकरण एवं प्लास्टिक पलवार की सुविधा होने पर इस तकनीक के प्रयोग से खुले खेत की तुलना में फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढाया जा सकता है। इस तकनीक से पानी की बचत, खाद की बचत, खरपतवार का नियंत्रण, मिटटी के तापमान का नियंत्रण एवं मजदूरी में कमी होती है। कम लागत के इस तकनीक को अपनाकर जाड़े के मौसम में कम तापमान एवं पाला पड़ने की स्थिति में भी बेहतर लाभ किसान ले सकते है। पिछले वर्ष रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित चोरियो गाँव के किसान लगातार कम तापमान एवं पाला पड़ने से परेशान थे। लगातार गिरते तापमान और पाला पड़ने की वजह से गाँव के करीब 100 एकड़ भूमि में किसान द्वारा पौध नर्सरी में लगाई गई तरबूज, प्याज, शिमला मिर्च व टमाटर के पौधे झुलस कर बर्बाद हो गए। मौसम की इस मार ने किसानों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी थी। गाँव के ही किसान नन्द किशोर साहू (नंदू) ने बीएयु वैज्ञानिक की सलाह मानकर एक एक-ड़ में तरबूज खेती हेतु लो टनल प्लास्टिक तकनीक से पौध पौध नर्सरी तैयार की। किसान नंदू बताते है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से उनके तरबूज पौध सामग्री सही सलामत रहा और इसमे ड्रिप इरीगेशन तकनीक से तरबूज की खेती काफी सफल रही। नंदू कहते है एक हजार की लागत से इस नई तकनीक को अपनाया और इसका नतीजा काफी लाभकारी रहा नंदू बताते है कि एक एकड़ में खेती हेतु पौध नर्सरी तैयार करने में शिमला मिर्च बीज पर करीब 25 हजार, तरबूज बीज पर 15 हजार, प्याज बीज पर 25 हजार तथा टमाटर बीज पर 4 हजार का खर्च पड़ता है। कम तापमान एवं पाला की वजह से बीज का अंकुरण नहीं हुआ और जहाँ अंकुरण हुआ, वहाँ के पौधे झुलस कर मर गए।

बीएयु वैज्ञानिक ने जाड़े में लो टनल प्लास्टिक तकनीक से पौध नर्सरी तैयार करने की बात कही थोड़े खर्च की बचत और वैज्ञानिक सलाह नहीं मानने से हमें जाड़े के इस मौसम में पौधे के झुलसने से काफी नुकसान उठाना पड़ा था।

मोती पालन सिखाते हैं मनवानी दंपति

एजेंसियां :कुलंजन और उनके पति, अशोक मनवानी पिछले 20 सालों से भारत में मोती पालन पर शोध कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र से संबंध रखने वाला यह दंपति अब तक महाराष्ट्र के अलावा और 12 राज्यों में मोती पालन कर चूका है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर-प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, असम आदि राज्यों में उन्होंने न सिर्फ़ खुद मोती पालन किया है पर बहुत से किसानों को सिखाया भी है।मनवानी दंपति ने साबित किया है कि मोती सिर्फ़ समुद्र के नमकीन पानी में ही नहीं बल्कि गाँव-शहरों में मीठे पानी के स्त्रोत जैसे नदी और तालाबों में भी हो सकता है।44 वर्षीय अशोक बताते हैं कि पढ़ाई के दिनों में उन्होंने लाइब्रेरी की एक किताब में मोती पालन के बारे में पढ़ा था। बस वहीं से उनकी दिलचस्पी इस विषय में हो गयी। इस बारे में और अधिक जानने की चाह उन्हें उनके गाँव से निकाल कर मुंबई ले आयी और फिर मुंबई से वे दिल्ली, भुवनेश्वर और कोचीन तक गए। इन जगहों पर स्थित कृषि संस्थानों से उन्होंने मोती पालन में सर्टिफाइड कोर्स और ट्रेनिंग की। इसके बाद अशोक ने खुद मोती पालन शुरू किया। उन्होंने बताया, ''मोती बनाकर बेचने से ज़्यादा रूचि मुझे इस प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने में रही। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा मोती पालन क-रके बेचूंगा, बल्कि मेरा उद्देश्य तो इस विषय पर शोध करके भारत में इसे किसानों के लिए हितकारी बनाना रहा है। और इसलिए मैंने अपने संगठन का नाम भी 'इंडियन पर्ल कल्चर' रखा है।''साल 2001 में उन्होंने 'इंडियन पर्ल कल्चर' को शुरू किया था और आज उसके बैनर तले वे सैकड़ों लोगों को मोती पालन के लिए ट्रेन कर चुके हैं।

ग्रामीण किसान मजदूर विकास समिति की बैठक संपन्न

शिव किशोर शर्मा समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नमीत हेमरोम राँची जिला अध्यक्ष चुने गये।

रांची : मोरहाबादी मैदान स्थित गाँधी स्मारक के समीप ग्रामीण किसान मजदूर विकास समिति की आवश्यक बैठक झारखण्ड प्रदेश अध्यक्ष, राजेश तिर्की के अध्यक्षता में बुलाई गई। इस बैठक में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों एवं किसानों के विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, साथ ही समिति का सर्वसम्मति से विस्तार किया गया, जिसमें शिव किशोर शर्मा को समिति का प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नमीत हेमरोम को ग्रामीण किसान मजदूर विकास समिति, राँची जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं शुभ कामनाएँ दी गई। इस बैठक में मुख्यरूप से प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिर्की, संरक्षक रवि कुमार पीटर, मुख्यअतिथि स्वरूप संजीव कुमार वर्मा, राहुल राज, अधिवक्ता एस.एस. प्रसाद आदि मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिर्की ने कहा यह सामाजिक संस्था है राजनीतिक नहीं है, जो केवल मजदूर एवं किसान के हित में कार्य करेगी। आज की बैठक में मुख्यरूप से राजेश तिर्की, रामजी, दिलीप कुमार, चरवा एक्का, सुनील कुमार रवि, सुरेन्द्र चौधरी व अन्य लोग उपस्थित थे।

251 जोड़ी सामुहिक विवाह करवायेगी नारी शक्ति सेना

नारी शक्ति सेना के प्रधान कार्यालय माउन्ट मोटर गली, रातु रोड़ में 21.12.2019 को बैठक हुई। बैठक में संस्था द्वारा 251 जोड़ी सामुहिक विवाह कराने पर चर्चा की गई जिसकी औपचारिक घोषणा 15.01.2020 के बाद कर दी जायेगी। संस्था के अध्यक्ष सुचिता तिवारी ने बताय इस बार सामुहिक विवाह में संस्था द्वारा अधिक से अधिक सहायता देने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा। सचिव राजेश कुमार ने नारी शक्ति सेना के दायित्व एवं योजनाओं को बताया एवं उपस्थित लोगो को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रवक्ता शिव किशोर शर्मा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजनओं के लाभ को बताया एवं लोगो को जन-जन तक इस योजनाओं को प्रचार करने को कहा । संस्था के महासचिव विशाल रंघुवशी ने गांव के लोगो तक सामुहिक विवाह के प्रचार के लिए टीम की घोषणा की। प्रकाश रंजन ने सरकार द्वारा लाये गयें सी.ए.ए. के बारे में विस्तार पुर्वक बताया एवं कहा समाज में इससे क्या फयादा होगा। आज की बैठक में मुख्यरूप से संस्था के सुमन मिश्रा, मुस्कान कुमारी, पुनम देवी,संध्या चैरसिया, अंजनी कुमारी,सुषमा मुण्डा, रेखा साहु, सरिता शर्मा, आशा देवी आदि उपस्थित थे।

कृषि शक्ति में ही किसानों की भक्ति : डॉ. राम शंकर कुरील

संवाददाता

रांचीः भारत में 'राष्ट्रीय किसान दिवस' प्रत्येक वर्ष 23 दिसम्बर को मनाया जाता है. यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है. उन्हें किसानों के अभूतपूर्व विकास के लिए याद किया जाता है.उनकी नीति किसानों व गरीबों को ऊपर उठाने की थी. उनका यह मत था कि बगैर किसानों को खुशहाल किए देश व प्रदेश का विकास नहीं हो सकता.उनकी मेहनत के कारण ही 'जमींदारी उन्मूलन विधेयक' 1952 में पारित हो सका. देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती है,जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है. भारतीय किसान खाद्यान्न देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी सहेज कर रखे हुए हैं. शहरों की अपेक्षा गांवों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अधिक देखने को मिलती है. किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है।

कृषि क्षेत्र के चहुमुखी विकास, अन्न उत्पादन एवं कृषि उत्पादों के भंडार को बढ़ाने के साथ - साथ

किसान की आय में बढ़ोतरी का प्रयास आज की जरूरत है. इसी आशय के साथ प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी की 75 वीं सालगिरह वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही और इसे एक चुनौती के रूप में लिया है. एक अच्छी रणनीति, सुनियोजित कार्यक्रम, पर्याप्त संसाधनों एवं कार्यान्वन में सुशासन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. कृषि के अतिरिक्त किसान के अन्य आय के साधनों जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, सूकरपालन, बकरीपालन, मधुमक्खीपालन, मछलीपालन एवं डेयरी के विकास की विभिन्न योजनाओं पर भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है. किसान की आय में वृद्धि के लिए इन अतिरिक्त आय स्त्रोतों के विकास के क्षेत्रों में प्रयास किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है. इसके लिये सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन, गोकुल मिशन, नीली क्रांति, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन आदि बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की है, जिनके कारण गत वर्षों में डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी, मत्स्यपालन के क्षेत्र में काफी वृद्धि दर्ज हुई है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में किसानों की आय दुगुनी करने हेतु गठित झारखण्ड राज्य-समन्वय समिति ने झारखण्ड राज्य की कृषि पारिस्थितिकी के अनुरूप विभिन्न मुद्दों जैसे कृषि मशीनीकरण, सिंचाई, बीज, कीट -नाशकों, उर्वरकों, विपणन, शोध एवं विकास, कृषि ऋण, जैविक खेती, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विस्तार जैसे विभिन्न मुद्दों पर निजी क्षेत्र, सरकारी संगठनों तथा किसान समूहों की परिचर्चाओं के आधार पर राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने का प्रारूप तैयार किया.किसानों के जीवन स्तर में सुधार देखने को राह कठिन जरूर है, परन्तु असंभव नहीं।

रांची रेल मंडल के चार कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत

राकेश शर्मा, तेज कुमार, प्रीतम समद और संजय कुमार चौरसिया को रेलवे ने उत्कृष्ट कार्य के पुरस्कृत किया

संवाददाता

रांची : को मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने राँची रेल मंडल के 4 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत किया। 2 कर्मचारियों को इम्पलॉई ऑफ द मंथ के लिये तथा 2 कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्य के लिये पुरुस्कृत किया गया।

राकेश शर्मा, वरिष्ठ गुड्स गार्ड को हटिया, मुरी से तुलीन स्टेशन जाने के बीच माल गाडी के 2 डब्बो के खुले दरवाज़े की सूचना समय पर तुलीन स्टेशन मास्टर को देकर दुर्घटना से बचाने के लिये इम्पलॉई ऑफ द मंथ से पु-रस्कृत किया गया।

तेज कुमार, मुख्य कार्यालय अधीक्षक (सामान्य) मंडल रेल प्रबंधक को उनके कर्तव्यनिष्ठा,एवं अनुशासित कर्मचारी होने के लिये पुरस्कृत किया गया। तेज कुमार सदैव रेल सेवा में तत्पर रहे हैं इसी कारणवश इन्हे इम्पलॉई ऑफ द मंथ से पुरुस्कृत किया गया।

प्रीतम समद को 64 कर्मचारियों के पदोन्नति, 2 कर्मचारियों की पात्रता सुनिश्चित करने तथा 21 कर्मचारियों को एम ए सी पी प्रदान करने का कार्य सफलता पूर्वक निर्धारित समय मे करने के लिये पुरस्कृत किया गया डसंजय कुमार चौर-सिया, वरिष्ठ लिपिक/कार्मिक विभाग को 47 आर आर सी (रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल) अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण एवं पद ग्रहण कार्यों तथा नये बहाल 47 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ निर्धारित समय सीमा के अंतरगत पूर्ण करने के लिये पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) अजीत सिंह यादव, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी नीरज कुमार एवं मंडल कार्मिक अधिकारी (प्रभारी) एस श्रीनिवास उपस्थित थे ।

असम के चाय बागानों में अब ड्रोन और रोबोट

प्लांटेशन लेबर एक्ट के मुताबिक, जहरीली खाद और कीटनाशकों के छि-ड़काव का काम करने वाले मजदूरों को दस्ताने, मास्क और चश्मा जैसे सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाने चाहिए. लेकिन गिने-चुने चाय बागानों में ही इस दिशानिर्देश पर अमल होता है. चाय मजदूर यूनियनों का आरोप है कि सुरक्षा उपकरणों के अभाव में हर साल इन जानलेवा बीमारियों की चपेट में आकर सैकड़ों मजदूरों की मौत हो जाती है. ऐसे में तकनीक के जरिए होने वाली इस नई पहल ने तमाम समस्याओं से जूझ रहे चाय उद्योग में उम्मीद की एक नई किरण तो पैदा कर ही दी है।

एजेंसियां :असम के चाय बागान अब ड्रोन और रोबोट को काम पर रखने जा रहे हैं. तकनीक की मदद से पत्तियां चुनने से लेकर कीटनाशक छिड़कने तक का काम होगा. मजदूरों की कमी से निबटने और उत्पादन बढ़ाने का यही रास्ता उन्हें ठीक लग रहा है। असम में विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे जर्जर चाय बागानों में मजदूरों की कमी से निपटने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा. इनमें आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल शामिल है. एआई तकनीक से बहाने रोबोटों के जरिए चाय की पत्तियां चुनी जाएंगी जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसी तरह ड्रोन के जरिए खतरनाक कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा. इससे काम जल्दी तो होगा ही, चाय मजदूरों को इन कीटनाशकों के खतरों से बचाने में भी सहायता मिलेगी. एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक असम कंपनी इंडिया लिमिटेड ने इस दिशा में पहल की है.

तकनीककाइस्तेमाल

अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर असम चाय के स्वाद में सुधार और बेहतरी के लिए तकनीक का सहारा लेने पर विचार हो रहा है. फिलहाल एक कंपनी ने इस दिशा में ठोस पहल कर दी है. अब जल्दी ही दूसरे चाय बागानों में भी आट-र्फिशियल इंटेलीजेंस आधारित इस तकनीक को अपनाने पर विचार चल रहा है. इसके तहत अब चाय की हरी पत्तियां चुनने में रोबोट की मदद ली जाएगी. इस-के साथ ही बागानों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोनों के जरिए किया जाएगा. इससे मजदूरों को इन कीटनाशकों के घातक असर से बचाया जा सकेगा.

इस तकनीक की शुरुआत करने वाली असम कंपनी इंडिया लिमिटेड का कहना है कि बीते 180 वर्षों से चाय बागानों में पौधे लगाने से लेकर पत्तियां चुनने और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए मजदू-रों पर ही निर्भर रहना होता था. लेकिन अब रोबोटिक ड्रोनों की सहायता से बीमार पौधों के इलाज के साथ ही बाकी तमाम काम भी किए जा सकेंगे. कंपनी का दावा है कि तकनीक के इस्तेमाल से बागान मजदूरों पर छंटनी का कोई खतरा नहीं है. उनको दूसरे कामों में लगाया जाएगा. कंपनी के एक प्रवक्ता बताते हैं, "फिलहाल तमाम बागानों में मजदूरों की भारी कमी है. प्रतिकूल हालातों और स्वास्थ्यजनित समस्याओं की वजह से मजदूरों के बच्चे अब बागानों में काम नहीं करना चाहते. तकनीक उनको बागान में काम करने के लिए आकर्षित करेगी.''कंपनी के पास फिलहाल 15 चाय बागान हैं. बीआरएस वेंचर्स के अध्यक्ष बीआर शेट्टी बताते हैं, "हमारा मकसद चाय उद्योग में आधुनिकतम तकनीक के इस्तेमाल से चाय की पत्तियों और मजदूरों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है. इसका असर हमारे बागानों के 26 हजार मजदूरों के साथ ही पूरे देश में चाय उद्योग में कार्यरत तमाम कर्मचारियों पर भी पड़ेगा.'' शेट्टी का कहना है कि यह परियोजना 'फिलहाल एक बागान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है. इसके कामयाब रहने के बाद देश के दूसरे चाय बागानों में बिना किसी पूंजी निवेश के मुफ्त तकनीकी सहायता की पेशकश की जाएगी. उन्होंने साफ किया कि तकनीक के इस्तेमाल से नौकरियों में कटौती नहीं होगी और मौजूदा 26 हजार कर्मचारी सरकार की ओर से तय 350 रुपए रोजाना की न्यूनतम मजदूरी पर काम करते रहेंगे. उनका इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में किया जाएगा.

बदलावकीउम्मीद

देश के अग्रणी चाय बागानों में से एक में तकनीक के इस इस्तेमाल से चाय मजूदरों की जिंदगी बदलने की उम्मीद की जा रही है. इस परियोजना में कंपनी के साथ मिल कर काम करने वाले अमेरिका स्थित स्मार्ट फार्म्स के नटराज बालासुब्रमण्यम बताते हैं, "हमने एशिया में ऐसी कई परियोजनाओं पर काम किया है. ऐसी परियोजनाएं मजदूरों का जीवन बेहतर बनाने के साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी काफी सहायक हैं.'' वह बताते हैं कि चाय बागानों में दो तरह के ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाएगा. इनमें से एक ड्रोन पौधों की हालत पर निगाह रखेगा और उनको स्वस्थ बनाने में सहायता करेगा. दूसरे किस्म के ड्रोन पौधों पर बेहद सटीक तरीके से कीटनाशकों का छिडकाव करेंगे.

टी बोर्ड के अध्यक्ष प्रभात बेजबरुआ को उम्मीद है कि यह तकनीक लगातार गिरती कीमतों, बढ़ते उत्पादन लागत और बूढ़े होते चाय के पौधों की वजह से खराब दौर से गुजर रहे चाय उद्योग में एक नई जान फूंकने में सहायता करेगी. बी.आर.शेट्टी कहते हैं, "हम ऐसी तकनीक ला रहे हैं जो कीटनाशकों के छि-ड़काव की वजह से कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों पर अंकुश लगाने में सहायता करेगा. यह तकनीक मजदूरों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी.'' फिलहाल चाय बागानों में कीटनाशकों के छिड़काव की वजह से मजदूरों में टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां आम हैं.कीटनाश-ाकों के छिड़काव की वजह से ज्यादातर चाय मजदूर इन दोनों बीमारियों की चपेट में हैं. ड्रोन के इस्तेमाल से मजदूरों को इन जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकेगा. इसके अलावा कीटनाशकों की बर्बादी भी रोकी जा सकेगी।

फोटो न्यूज

जहां प्लास्टिक हमारे लिये खतरा बना हुआ है, वहीं कुछ उपयोगी सामान भी इससे बनायी जा सकते हैं। कचड़े में फेंकने के बजाय प्लास्टिक बोतल से बना ये गुलदस्ता

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में मंडल के कर्मचारियों द्वाय क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया । इस मिलन समारोह के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधकनीरज अम्बष्ठ ने ढोल बजाते हुए

तनाव से मुक्ति देते हैं गुलदाउदी के फूल

गुलदाउदी संसार के सबसे प्रसिद्ध एवं शरद ऋतु में फूलनेवाले पौधों में से है। यह चीन का देशज है, चीन के एक मनोवैज्ञानिक ने शोण कर यह बताया है कि पीले गुलदाउदी के फूलों को निहारने से किसी व्यक्ति का अवसाद कम होता है। से जहाँ से यह यूरोप में भेजा गया। सन 1780 में फ्रांस के एक महाशय सेल्स ने इंग्लैंड के विश्वविख्यात उपवन क्यू में इसे सबसे पहले उत्पन्न किया। इसके उपरांत, अपने सुंदर तथा मोहक रूप के कारण और इसके फूलों में कीटनाशक पदार्थ, अर्थात पाईथ्रोम होने के कारण गुलदाउदी का प्रसार बहुत ही विस्तृत हो गया। इस समय इसकी लगभग 150 जातियाँ हैं जो यूरोप, अमरीका, अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। गुलदाउदी का पौधा शाक की श्रेणी में आता है। सुंदरता के साथ साथ गुलदाउदी की कुछ जातियों के फूल कीटनाशक गुणवाले होते हैं। सबसे पहले ईरान मेंइसके फूल कीटनाशक रूप में प्रयुक्त हुए। डलमैशिया जाति के गुलदाउदी यूगोस्लाविया में उत्पन्न की गई और धीरे धीरे इसने ईरानी जातियों से ज्यादा ख्याति प्राप्त कर ली। व्यापारिक स्तर पर गुलदाउदी की खेती ईरान, अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड तथा भारत में की जाती है। भारत में हाल के कुछ सालों में गुलदाउदी आम लोगों के बगीचों और लॉन की शोभा बढा रहे हैं। पहले यह उतने आम नहीं थे। गुलदाउदी के पौधे की अगर जाड़े के मौसम के बाद भी थोड़ी सी देख भाल की जाये तो यह अगले जाड़े में फिर से स्वस्थ आकार ले लेता है और इस पर खुबसूरत फूल आ जाते हैं।

पिकनिक मनाइये लेकिन स्पॉट पर हुड़दंग और कचड़ा मत फैलाइये

देवाशीष राय

रांची:नया साल आने ही को है। हम झारखंडी बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारा राज्य बहुत खुबसूरत है और सिर्फ रांची के आस पास ही दर्जनों पिकनिक स्पॉट हैं। जोन्हा, दशम, सीता, हिरणी, पंचघाघ, हुंडरू जैसे जलप्रपातों के अलावा कई डैम, पहाड़, मंदिर और रमणिक स्थान भी हैं। नये साल के आगमन से पूर्व ही इन स्थानों पर मित्रों के साथ या सपरिवार लोग जाते हैं। हां खाते पीते हैं और मौज मस्ती कर महंगी गाड़ियों में बैठ कर वापस अपने घर को चल देते हैं, लेकिन इन पिकनिक स्पॉटों पर वो अपने पीछे कचड़े का ढेर छोड़ जाते हैं। इसमें प्लास्टिक के ग्लास, बोतल थर्मोकोल के प्लेट वगैरह होते हैं। ये अपने आप में एक शर्म की बात है कि हम जिस जगह की खुबसूरती से खिंचे चले आते हैं उसी जगह को कचड़े से पाट कर चल देते हैं आगे किसी और साफ सुथरी जगह को बर्बाद करने के लिये। ये हाल सिर्फ रांची का नहीं है बल्कि कमोबेश पूरे झारखंड के पिकनिक स्पॉटों की यही हालत है। पिछले साल जनवरी में देवघर के सभी पिकनिक स्पॉटों पर काफी भीड़ रही लेकिन साफ सफाइ न होने और पर्यटकों के फैलाये गये कचड़े के कारण ये सारे स्पॉट गंदगी से पटे रहे थे।एक खबर के अनुसार पर्यटन स्थलों पर सफाई व डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी नंदन पहाड़ व त्रिकुट पहाड़ पर डस्टबिन का प्रबंध नहीं रहने के कारण पिकनिक स्पॉट पर लोग गंदगी छोड़कर चले गये वहीं दूसरे दिन सफाई नहीं होने से पर्यटन स्थलों की खूबसूरती पर दाग लग रहा था। देवघर का वाकया सिर्फ उदाहरण है, बाकी जगहों पर भी यही हाल रहा। राज्य में एक ट्रेंड है कि कहीं पर्यटकों की आवक बढी नहीं कि उस जगह को कंक्रीट के निर्माण से पाट दिया जाता है, फिर वहां दूकान और बाजार लगने लगते हैं और अंततः वहं शांत सुरम्य जगह बर्बाद हो जाता है।

ज्यादतर पर्यटकों में सिविक सेंस की कमी है

हाल के कुछ सालों में लोगों की क्रय शक्ति और आमदनी बढी है। इस कारण से पिछले एक दशक में सपरिवार अपने चारपहिया वाहनों से घूमने की प्रवृति भी बढी है। जनवरी में लोग परिवार के साथ पिकनिक स्पॉटों पर पहुंचते तो हैं, पर वहां कचड़ा फैलाने से परहेज करने वाले बहुत कम परिवार होते हैं। सपरिवार जाने वाले मौज मस्ती तो खूब करते हैं लेकिन अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते कि कचड़े को यहां वहां न फेंके। बेतरतीब गाड़ी पार्क करने से लेकर खाने पीने के दरम्यान पिकनिक स्पॉटों पर प्लास्टिक, बोतल, प्लेट वगैरह यूं हीं फेंक कर चल देना पर्यटकों की फितरत सी बन गयी है।आइये वर्ष 2020 में हम इसे रोकने का प्रयास करें।

प्लास्टिक और शराब के बोतलों से पट जाते हैं पिकनिक स्पॉट

नये साल का आगमन कुछ लोगों और युवाओं के लिये शराबखोरी का बहाना बन जाता है। ऐसे लोग अपने पीने खाने के इंतजाम के साथ झुंड में पिकनिक स्पॉटों पर पहुंचते हैं। पी खा कर माहौल खराब करने के साथ ही शराब की बोतलों और प्लासिटक के ग्लास से उस जगह पर कचड़ा कर ये चलते बनते हैं। हुंडरू फॉल हो या कोई और फॉल झारखंड के सभी पिकनिक स्पॉटों पर यत्र- तत्र शराब की बोतलों का दिखना आम बात है। इनमें कुछ हुड़दंगी और पियक्कड़ तो ऐसे भी होते हैं कि खाली शराब की बोतलों को फोड़ कर जाते हैं। इससे चारो ओर कांच बिखर जाता है जो और भी खतरनाक है। हर साल पिकनिक के मौसम में शराब के नशे में वाहन चलाने से दुर्घटना में किसी के घर के चिराग के बुझने की दुखद खबर भी आती है ।ग्रीन रिवोल्ट ये आह्वान करता है कि आप नये साल में खुब मौज मस्ती करें, पर किसी और के लिये परेशानी खड़ी न करें।

नुकसानदेह है मांगुर मछली का पालन

मनोज कुमार शर्मा

रांची: मांसाहार में सबसे उत्तम मछली को माना गया है। पहले झारखंड में मछलियां दूसरे राज्यों से आती थीं लेकिन हाल के कुछ सालों में झारखंड मतस्यपालन में आत्म निर्भर हुआ है और मत्स्य विभाग के प्रयासों के कारण राज्य के झीलों, तालाबों , नदियों में हीं पर्याप्त मछली उत्पादन होने लगा है। अब हालात ऐसे हैं कि रोहू, कतला मृगल जैसी मछलियां हम जिंदा खरीद सकते हैं। ऐसी ही एक मछली है मांगुर यानि कैटफिश जिसे हम सदा से देखते आ रहे हैं कि उसे मछली बेचने वाले बड़े से हंडिया में पानी में डाल कर जीवित ही बेचते हैं।

यह बिना शल्क वाली चिकनी मछली है और कहा जाता है कि किसी कमजोर वयक्ति को खिलाने से उसे जल्दी ही शक्ति प्राप्त होती है। मछलियों से हमें स्वास्थ्यवर्द्धक ओमेगा3 तेल प्राप्त होता है वहीं मांगुर से हमें ओमेगा6 प्राप्त होता है। लेकिन इन फायदों के एवज में मांगुर मछली का पालन हमारे तालाबों, झीलों के इकोसिस्टम के लिये खतरनाक है और इस पर बैन लगा दिया गया है।

मांगुर मछली की एक खासियत होती है कि यह प्रमिकूल परिस्थति में भी सर्वाइव कर जाती है। यानि कम पानी या ऑक्सीजन में भी यह जिंदा रह लेती है। और यह जिस तालाब या जल में रहती है वहां किसी और मछली का सफाया कर डालती है। खास कर विदेशों से आयी थाई मांगुर या अफ्रिकन मांगुर बहुत ही खतरनाक है। एक तालाब में अगर आपने विदेशी मांगुर मछली पाल ली तो ये उसके पूरे पारिस्थतिकी तंत्र को पक्का बर्बाद कर देंगी। ये अन्य मछलियों के बजाय तेजी से बढती हैं, मांसाहार और शिकारी प्रवृति होने के कारण ये किसी और जलीय जीव या मछली को पनपने नहीं देंगी। तालाब में ज्यादा संख्या में मांगुर हो तो ये मनुष्यों पर भी हमले कर देती हैं।

देशी स्वादिष्ट मांगुर अब बाजारों से तकरीबन गायब

पहले देशी मांगुर हाट बाजारो में मिलते थे जिनका रंग ज्यादा गहरा या कुछ कत्थई सा होता था। ये थाई मांगुर की तरह तेजी से बड़े नही होते थे और न ही ये जलाशयों के पारिस्थतिकी के लिये कोई बड़ा खतरा थे। इसके अलावा इनका स्वाद भी विदेशी मांगुरों से अच्छा था। नब्बे के दशक में मछली पालन के चक्कर में विदेशी नस्ल के थाई और अफ्रिकन मांगुर के बीजों का आयात किया गया मुख्यतः ये बांग्लादेश से मंगाये गये। इन विदेशी मांगुर मछलियों का आकार तेजी से बढता देख प्रारंभ में इसे तालाबों नदियों में पाला गया, लेकिन जल्दी ही पाया गया कि ये हल्के रंग वाले विदेशी मांगुर मछली तो पूरे इकोसिस्टम के लिये खतरनाक हैं ये और किसी मछली को पालने की उम्मीद ही खत्म कर दे रहे हैं। इस कारण से पहले केरल सरकार ने इस पर बैन लगा दिया और पालने पर सजा का प्रावधान भी कर दिया गया। इन विदेशी मांगुर मछलियों का स्वाद भी अच्छा नही है। आज इसके नुकसान को देख कर प्राकृतिक जलाशयों में इसे पालने से परहेज किया जा रहा है आखिर यह खतरनाक और नुकसानदेह विदेशी प्रजाति हमारी अन्य स्वादिष्ट रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों को नष्ट जो कर दे रही है।

निपाह वायरस के इलाज की दवा बनाने के करीब पहुंचे भारतीय वैज्ञानिक

अभी निपाह वायरस से होने वाली बीमारी के लिए टीके या दवा नहीं है, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक इसके करीब पहुंच गए हैं। निपाह वायरस चमगादड़ और सूअरों से मनुष्यों में फैलता है। इस वायरस की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी तक इसके उपचार के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएं नहीं हैं। शोधकर्ताओं ने वायरस के 150 संभावित अवरोधकों (इन्हिबटर) की पहचान करने के लिए निपाह वायरस की संरचना का उपयोग किया है। यह शोध प्लोस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीसेस नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

इस नए शोध में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के एम.एस. मधुसूदन और उनके सहयोगियों ने सबसे पहले निपाह वायरस प्रोटीन के तीन मॉडल बनाए। फिर, उन्होंने प्रोटीन की गतिविधि को अवरुद्ध करने के लिए इन मॉडलों से अणुओं का उपयोग किया, ताकि वायरस के प्रभाव को रोका जा सके। अंत में, टीम ने इस प्रयोग को वायरस के 15 अलग-अलग नस्लों (स्ट्रेनस) के खिलाफ इसके प्रभाव को जानने के लिए किया। इन 15 नस्लों (स्ट्रेनस) में से 3 बांग्लादेशी, 7 मलेशियाई और 5 भारतीय है। शोधकर्ताओं ने गणना करके निपाह वायरस के प्रोटीन के खिलाफ, 4 रुकावट डालने वाले पेप्टाइड और 146 छोटे अणु इन्हिबटर की पहचान की है। अवरोधकों में निपाह वायरस के अलग-अलग नस्लों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान को रोकने की ताकत, और प्रभावशीलता के आधार पर इन्हें सूचीबद्ध किया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि अवरोधक वायरस निपाह और अन्य संबंधित जूनोटिक वायरस के सभी नस्लों के खिलाफ असरदार होंगे। इस तरह के वायरस गंभीर महामारी का खतरा पैदा करने वाले होते हैं।

E ZONE CARE

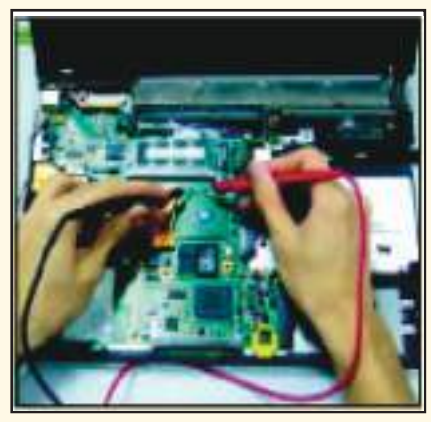

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

स्पेन कांफ्रेंसः बेनतीजा रही पर्यावरण पर चिंता

एजेंसियां

पर्यावरण को लेकर विकसित देश कितने संजीदा हैं, यह स्पेन के मैड्रिड में हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज-कॉप-25-को देखने-समझने से पता चलता है। दो सप्ताह और अतिरिक्त 40 घंटे खर्च करने के बावजूद 200 देशों के नेता, नौकरशाह और पर्यावरण की घोर चिंता करने वाले पर्यावरणविद किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सीधे शब्दों में पर्यावरण को लेकर आयोजित यह बड़ा सम्मेलन बिना किसी सकारात्मक परिणाम के रहा। निराशा इस मायने में बड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बिना लाग-लपेट के कहा कि दुनिया ने बड़ा मौका गंवा दिया। हम हार नहीं मानेंगे। मैं तो हर्गिज नहीं मानूंगा। न्यूयार्क की डेमोक्रेट कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रा ओकासियो कोर्टेज का कथन ज्यादा मारक है। अलेक्जेंड्रा ने कहा कि कॉप-25 जैसा सम्मेलन दरअसल पर्यावरण से जुड़ी चर्चाओं के लिए अहम मंच है ना कि नेताओं के मजे के लिए कॉकटेल पार्टी जैसे आयोजन के लिए। ऐसे निराशाजनक बयान स्पष्ट तौर पर इंगित करते हैं कि पर्यावरण को लेकर विकसित देशों का नजरिया कितना संकुचित है। जबकि

ग्लोबल वार्मिग के एक्शन को लेकर मैड्रिड में संपन्न सम्मेलन में मौजूद देशों से उम्मीद थी कि वे इस पर कोई साफ और सरल घोषणा करेंगे। मानवता का अस्तित्व दांव पर है, ऐसे में पहले से ज्यादा और बेहतर करने का इरादा दिखाने की उम्मीद थी। यह भी आशा थी कि कॉप-25 के अंतिम घोषणापत्र में पूरी दुनिया से अगला साल खत्म होने से पहले जलवायु आपातकाल (क्लाइमेट इमरजेंसी) से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की अपील करेंगे, पर इसमें कुछ खास नहीं हुआ। सम्मेलन में इन विकल्पों को कई देशों ने गैर जरूरी माना। यह तय किसी से छुपा या अनजान नहीं है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के उपाय करना या उपाय तलाशना एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते पृवी लगातार गर्म हो रही है। 2015 के पेरिस समझौते में सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास का भरोसा दिलाया था, मगर इन कोशिशों का नतीजा ये है कि पृवी की गर्मी उल्टे 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि पेरिस समझौता 2020 से प्रभावी होना है। संयुक्त राष्ट्र पैनल का मानना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी मुश्किलों को आमंतग्रदेने जैसा है। पूरी दुनिया के लोग इस खतरे से वाकिफ हैं और इसी कारण अलग-अलग देशों के युवाओं ने मार्च निकाला, ताकि उनकी सरकारों तक बात पहुंचे, लेकिन जब दुनिया को स्पष्ट संदेश देने की बारी आई तो मैड्रिड सम्मेलन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इसमें सिर्फ पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और प्रयास करने की अपील भर की गई। इस घोषणा के शब्दों पर ही कई दिनों तक चर्चा होती रही। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यूनतम करने पर चर्चा नाममात्र की हुई। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश अपनी जवाबदेही से भागते नगर आए। जहां तक भारत की बात है, पेरिस समझौते के तहत भारत इस बात पर राजी हुआ था कि कार्बन उत्सर्जन की रफ्तार 2030 तक 33 से 35 फीसद तक कम करेगा। इसके साथ 3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड प्रभावित क्षेत्र को जंगल और पौधों से भरेगा। चीन और अमेरिका के बाद भारत ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स, चावल की खेती और पशु इस उत्सर्जन के सबसे बड़े कारक हैं और इसमें तेजी से बढ़ोत्तरी जारी है। 2002 में, भारत ने नई दिल्ली में (यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लामेट चेंज) से संबंधित आठवें आधिकारिक बैठक का आयोजन और उसकी अगुवाई की थी। इस बैठक में दिल्ली मिनिस्ट्रियल घोषणापत्र को अपनाया गया था। इसमें विकसित देशों से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की अपील की गई थी, जिससे विकासशील देशों को उत्सर्जन में कमी लाने और खुद को जलवायु परिवर्तन के मुताबिक ढालने में उसे मदद मिले। 2017 में किए गए एक और सर्वे से ये बात सामने आई कि 47 फीसद भारतीय जलवायु परिवर्तन को अपने देश के लिए ''बड़ा खतरा' मानते हैं। अगर दुनिया के तथाकथित विकसित देशों द्वारा अपने रवैये में बदलाव नहीं लाया गया तो पृवी पर तबाही तय है। पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की जगह विकसित (धनी) देश मामूली काम करते हैं। इससे समस्या जस-की-तस बनी हुई है। कोयले की ''खल' भूमिका के बारे में जानने के बावजूद एक साल के यह मसला टल गया है। अब ग्लासगो में इस पर चंचा होगी। तब तक ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से दो-चार होते रहना होगा।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।